



"समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से जातिवाद का अध्ययन"

Dr. Jitendra Kumar

Associate Professor, Dept. of Sociology
S. M. College Chandausi

सारांश

जातिवाद, कई समाजों में, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में, प्रचलित एक गहरी जड़ जमाई हुई सामाजिक पदानुक्रम है, जो समाजशास्त्र के भीतर अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। यह विश्लेषण विभिन्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों के माध्यम से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, निरंतरता और प्रभावों की जांच करता है। यह पता लगाता है कि जाति-आधारित स्तरीकरण सामाजिक अंतःक्रियाओं, संसाधनों तक पहुँच और व्यक्तिगत पहचान को कैसे आकार देता है। अध्ययन जातिवाद के ऐतिहासिक विकास, इसके धार्मिक और सांस्कृतिक आधार और जाति विभाजन को बनाए रखने में संस्थागत और संरचनात्मक कारकों की भूमिका पर गहराई से विचार करता है। **बी.आर. अंबेडकर, लुइस ड्यूमॉन्ट और एम.एन. श्रीनिवास** सहित प्रमुख समाजशास्त्रियों के सैद्धांतिक दृष्टिकोणों को एकीकृत करके, यह शोध जाति गतिशीलता की जटिलताओं और जाति-आधारित भेदभाव का मुकाबला करने में लगातार चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा, विश्लेषण डिजिटल युग में जाति, अन्य सामाजिक पहचानों के साथ अंतर्संबंध और जातिवाद के वैश्विक आयामों जैसे समकालीन मुद्दों को संबोधित करता है। निष्कर्ष जाति पदानुक्रम को खत्म करने और सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीतियों और सामाजिक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

कीवर्ड: जातिवाद, सामाजिक पदानुक्रम, समाजशास्त्र, दक्षिण एशिया, सामाजिक स्तरीकरण

परिचय

जातिवाद, सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यापक और गहरी जड़ वाली प्रणाली, लंबे समय से समाजशास्त्रीय जांच का विषय रही है। दक्षिण एशिया में मुख्य रूप से देखी जाने वाली, विशेष रूप से भारत में, जाति व्यवस्था समाज को जन्म के आधार पर कठोर पदानुक्रमित समूहों में संगठित करती है। ये समूह, या जातियाँ, किसी व्यक्ति के जीवन के कई पहलुओं को निर्धारित करती हैं, जिसमें सामाजिक संपर्क, आर्थिक अवसर और संसाधनों तक पहुँच शामिल है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का पता प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों में लगाया जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव समकालीन समाज में गहराई से महसूस किए जाते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जातिवाद को समझने में उन जटिल तरीकों की जांच करना शामिल है जिनसे जाति सामाजिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को आकार देती है **श्रीनिवास** ने जाति व्यवस्था के कामकाज और उसके स्थायित्व के बारे में आधारभूत अंतर्दृष्टि प्रदान की है। उत्पीड़न के एक उपकरण के रूप में जाति के बारे में **अंबेडकर** का आलोचनात्मक विश्लेषण,

जाति विचारधारा के बारे में ड्यूमॉन्ट की खोज और श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा और जाति गतिशीलता में इसकी भूमिका इस क्षेत्र में मौलिक योगदान हैं। जातिवाद न केवल व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तियों को प्रभावित करता है, बल्कि व्यापक सामाजिक गतिशीलता के लिए भी महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है। यह विवाह, शिक्षा, व्यवसाय और राजनीतिक शक्ति के पैटर्न को प्रभावित करता है। जाति-आधारित भेदभाव के संस्थागतकरण ने कई हाशिए के समुदायों के लिए प्रणालीगत असमानताओं, गरीबी और सामाजिक बहिष्कार को बढ़ावा दिया है। समकालीन समय में, लिंग और वर्ग जैसी अन्य सामाजिक पहचानों के साथ जाति का प्रतिच्छेदन विश्लेषण में जटिलता की परतें जोड़ता है। डिजिटल प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के आगमन ने जाति की गतिशीलता में नए आयाम पेश किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जातिगत पूर्वाग्रहों को बनाए रखने और जातिगत भेदभाव को चुनौती देने दोनों के लिए जगह बन गए हैं। इसके अलावा, वैश्विक प्रवासी जाति के मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में लाते हैं, जो जातिवाद की वैश्विक समझ की आवश्यकता को उजागर करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य ऐतिहासिक और समकालीन परिप्रेक्ष्यों का उपयोग करते हुए जातिवाद की बहुआयामी प्रकृति का पता लगाना है। यह उन तंत्रों को समझने का प्रयास करता है जिनके माध्यम से जाति व्यवस्था को बनाए रखा जाता है और उन्हें खत्म करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को समझना चाहता है। जाति-आधारित असमानताओं की निरंतरता और डिजिटल युग में उभरती चुनौतियों दोनों को संबोधित करते हुए, यह विश्लेषण सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर समाजशास्त्रीय शोध और सामाजिक सुधारों के महत्व को रेखांकित करता है।

❖ जाति और सामाजिक स्तरीकरण

जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है जो लोगों को विरासत में मिली स्थिति के आधार पर पदानुक्रमित समूहों में संगठित करती है। यह स्तरीकरण उन समाजों के सामाजिक ताने-बाने में गहराई से समाया हुआ है जहाँ जाति व्यवस्थाएँ प्रचलित हैं, जैसे कि भारत में। वर्ग-आधारित स्तरीकरण के विपरीत, जो आर्थिक गतिशीलता से प्रभावित और परिवर्तनशील हो सकता है, जाति-आधारित स्तरीकरण कठोर और वंशानुगत है, जिसमें ऊपर की ओर बढ़ने के सीमित अवसर हैं।

❖ जाति-आधारित स्तरीकरण की विशेषताएँ

1. **वंशानुगत स्थिति:** जाति की सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है, और व्यक्ति अपने माता-पिता से अपनी जाति की स्थिति विरासत में प्राप्त करते हैं। यह स्थिति उनकी सामाजिक स्थिति और अक्सर उनके व्यवसाय को निर्धारित करती है।
2. **अंतर्विवाह:** विवाह आमतौर पर एक ही जाति के सदस्यों तक सीमित होते हैं, जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अलगाव को मजबूत करते हैं।
3. **व्यवसाय:** पारंपरिक जाति व्यवस्थाएँ विशेष जातियों को विशिष्ट व्यवसाय सौंपती हैं, जिससे अक्सर श्रम का विभाजन होता है जिसे सख्ती से बनाए रखा जाता है।

4. **सामाजिक संपर्क:** विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक संपर्क मानदंडों और रीति-रिवाजों द्वारा विनियमित होते हैं, जिनमें अक्सर शुद्धता और प्रदूषण के बारे में सख्त नियम शामिल होते हैं।

❖ सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव

जाति-आधारित स्तरीकरण सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, जिसमें शामिल हैं:

- **शिक्षा:** निम्न-जाति के व्यक्तियों के लिए शिक्षा तक पहुँच गंभीर रूप से सीमित हो सकती है, जिससे गरीबी और अवसरों की कमी का चक्र चलता रहता है।
- **आर्थिक अवसर:** आर्थिक गतिविधियाँ और नौकरी के अवसर अक्सर जाति-विशिष्ट होते हैं, जो आर्थिक गतिशीलता को सीमित करते हैं और आर्थिक असमानताओं को मजबूत करते हैं।
- **सामाजिक गतिशीलता:** जाति व्यवस्था की कठोर प्रकृति सामाजिक गतिशीलता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करती है, जिससे स्थापित पदानुक्रम और असमानताएँ बनी रहती हैं।
- **राजनीतिक शक्ति:** जाति राजनीतिक शक्ति गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है, जिसमें कुछ जातियाँ राजनीतिक संस्थाओं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर हावी होती हैं।

❖ सैद्धांतिक दृष्टिकोण

- **बी.आर. अंबेडकर:** अंबेडकर ने सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न के साधन के रूप में जाति व्यवस्था की आलोचना की, सच्चे सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए जाति के विनाश की वकालत की।
- **लुइस इयूमॉन्ट:** इयूमॉन्ट का काम जाति के वैचारिक और धार्मिक आधारों, विशेष रूप से शुद्धता और प्रदूषण की अवधारणा पर केंद्रित था।
- **एम.एन. श्रीनिवास:** श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा पेश की, जिसमें बताया गया कि कैसे निचली जातियाँ उच्च जातियों की प्रथाओं को अपनाकर अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करती हैं।

❖ समकालीन मुद्दे

आधुनिक समाज में, समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कानूनी ढाँचे के बावजूद, जाति-आधारित स्तरीकरण विभिन्न रूपों में प्रकट होता रहता है। जाति के आधार पर भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। डिजिटल तकनीक के उदय ने जाति की गतिशीलता को भी बदल दिया है, जिसमें सोशल मीडिया जाति-आधारित भेदभाव को बनाए रखने और चुनौती देने दोनों के लिए एक मंच प्रदान करता है।

इन गहरी असमानताओं को दूर करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जाति और सामाजिक स्तरीकरण को समझना आवश्यक है। जाति व्यवस्था के ऐतिहासिक और समकालीन आयामों का विश्लेषण करके, समाजशास्त्री इन पदानुक्रमों को खत्म करने और अधिक समतावादी समाजों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रयासों में योगदान दे सकते हैं।

❖ समकालीन समाज में जाति

महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक प्रगति के बावजूद, जाति समकालीन समाज में, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में, एक व्यापक शक्ति बनी हुई है। जाति व्यवस्था की कठोर पदानुक्रमित संरचना सामाजिक संपर्क, आर्थिक अवसर, राजनीतिक शक्ति और व्यक्तिगत पहचान सहित दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती रहती है। जाति-आधारित भेदभाव और असमानता की चल रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए जाति की आधुनिक अभिव्यक्तियों को समझना महत्वपूर्ण है।

❖ जाति-आधारित भेदभाव की निरंतरता

1. **आर्थिक असमानता:** जाति आर्थिक स्थिति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती है। निम्न-जाति के व्यक्तियों को अक्सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक असमानताएँ होती हैं जिन्हें दूर करना मुश्किल होता है।
2. **शैक्षिक बाधाएँ:** हालाँकि जातिगत असमानताओं को दूर करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ लागू की गई हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में असमानताएँ बनी हुई हैं। निम्न-जाति के छात्रों को अक्सर शैक्षिक सेटिंग्स में भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।
3. **राजनीतिक प्रभाव:** जातिगत पहचान राजनीतिक संबद्धता और मतदान व्यवहार को आकार देना जारी रखती है। जाति-आधारित राजनीति प्रचलित है, जिसमें राजनीतिक दल अक्सर समर्थन जुटाने के लिए विशिष्ट जाति समूहों से अपील करते हैं। यह जाति विभाजन को कायम रख सकता है और सामाजिक सामंजस्य की दिशा में प्रयासों में बाधा डाल सकता है।
4. **सामाजिक बहिष्कार:** कई ग्रामीण क्षेत्रों में, छुआछूत और अलगाव जैसी पारंपरिक जाति प्रथाएँ अभी भी प्रचलित हैं। शहरी परिवेश में भी, निम्न-जाति के व्यक्तियों को आवास, सामाजिक नेटवर्क और सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव के सूक्ष्म रूपों का सामना करना पड़ सकता है।

❖ अंतर्विभाजन और जाति

जाति का लिंग, वर्ग और धर्म जैसी अन्य सामाजिक पहचानों के साथ अंतःविभाजन, जाति-आधारित भेदभाव के अनुभव को जटिल बनाता है। उदाहरण के लिए:

- **लिंग और जाति:** निम्न जातियों की महिलाओं को अक्सर उनके लिंग और जाति की स्थिति के आधार पर दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक और आर्थिक नुकसान होता है।
- **वर्ग और जाति:** जबकि वर्ग गतिशीलता कुछ हद तक संभव है, जाति अक्सर वास्तविक आर्थिक उन्नति में बाधा के रूप में कार्य करती है। निम्न-जाति के व्यक्ति जो आर्थिक सफलता प्राप्त करते हैं, उन्हें अभी भी सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है।

- **धर्म और जाति:** कुछ धार्मिक समुदायों में, जातिगत भेदभाव प्रभावशाली बने हुए हैं, जो उन समुदायों के भीतर धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं।

डिजिटल युग और जातिगत गतिशीलता

डिजिटल प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के आगमन ने जातिगत गतिशीलता के नए आयाम पेश किए हैं। एक ओर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जातिगत पूर्वाग्रहों को बनाए रख सकते हैं और जाति के आधार पर ऑनलाइन उत्पीड़न की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। दूसरी ओर, ये प्लेटफॉर्म निचली जाति के व्यक्तियों को जागरूकता बढ़ाने, सामाजिक न्याय के लिए जुटने और व्यापक कार्यकर्ता नेटवर्क से जुड़ने के लिए एक स्थान भी प्रदान करते हैं।

- **डिजिटल सक्रियता:** #DalitLivesMatter जैसे ऑनलाइन अभियान और सोशल मीडिया आंदोलनों ने जाति-आधारित भेदभाव और हिंसा पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है, जिससे हाशिए पर पड़े समुदायों की आवाज़ बुलंद हुई है।
- **प्रौद्योगिकी तक पहुँच:** डिजिटल विभाजन मौजूदा जातिगत असमानताओं को बढ़ा सकता है, जिसमें निचली जाति के व्यक्तियों के पास अक्सर डिजिटल संसाधनों और इंटरनेट तक कम पहुँच होती है।

प्रयास और सुधार

जाति-आधारित असमानताओं को दूर करने के प्रयासों में कानूनी ढाँचे, सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ और सामाजिक जागरूकता अभियान शामिल हैं। हालाँकि, इन उपायों को क्रियान्वयन और प्रवर्तन में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- **कानूनी ढाँचा:** भेदभाव-विरोधी कानून और नीतियों का उद्देश्य निम्न-जाति के व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार से बचाना है। हालाँकि, प्रवर्तन असंगत बना हुआ है, और सामाजिक दृष्टिकोण अक्सर कानूनी सुरक्षा को कमजोर करते हैं।
- **सकारात्मक कार्रवाई:** शिक्षा और रोजगार में आरक्षण नीतियों ने निम्न-जाति के व्यक्तियों को अवसर प्रदान किए हैं। फिर भी, इन नीतियों पर अक्सर विवाद होता है और ये गहरी जड़ें जमाए बैठी असमानताओं को दूर करने के लिए अपर्याप्त हो सकती हैं।
- **सामाजिक जागरूकता:** शिक्षा और जागरूकता अभियान का उद्देश्य जाति के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को चुनौती देना और बदलना है। प्रमुख समाज सुधारक और कार्यकर्ता जाति-आधारित भेदभाव के उन्मूलन की वकालत करना जारी रखते हैं।

निष्कर्ष रूप से, जाति समकालीन समाज में एक महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दा बनी हुई है। जबकि प्रगति हुई है, जाति-आधारित भेदभाव और असमानता की निरंतरता सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर समाजशास्त्रीय अनुसंधान और लक्षित प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। जाति की आधुनिक अभिव्यक्तियों को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की



आवश्यकता है जो सामाजिक पहचानों की अंतःक्रियाशीलता और डिजिटल युग की उभरती गतिशीलता पर विचार करता हो।

निष्कर्ष

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जातिवाद का अध्ययन समाजों पर जाति-आधारित सामाजिक स्तरीकरण के स्थायी और व्यापक प्रभाव को प्रकट करता है, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में। महत्वपूर्ण कानूनी प्रगति और सामाजिक सुधारों के बावजूद, जाति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक बनी हुई है। इस विश्लेषण ने ऐतिहासिक संदर्भों, सैद्धांतिक रूपरेखाओं और समकालीन चुनौतियों पर आधारित जाति गतिशीलता की जटिलताओं को उजागर किया है। जातिवाद ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में गहराई से निहित है, सामाजिक पदानुक्रम को कायम रखता है और भेदभाव को संस्थागत बनाता है। बी.आर. अंबेडकर, लुइस इयूमॉन्ट और एम.एन. श्रीनिवास जैसे अग्रणी समाजशास्त्रियों ने उन तंत्रों में आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान की है जिनके माध्यम से जाति व्यवस्था संचालित होती है और बनी रहती है। उनके योगदान से हमें जाति की वैचारिक और संरचनात्मक नींव, साथ ही सामाजिक गतिशीलता और सुधार के संभावित मार्गों को समझने में मदद मिलती है। समकालीन समाज में, जाति-आधारित भेदभाव आर्थिक असमानताओं और शैक्षिक बाधाओं से लेकर सामाजिक बहिष्कार और राजनीतिक हाशिए पर जाने तक विभिन्न रूपों में प्रकट होता रहता है। जाति का लिंग और वर्ग जैसी अन्य सामाजिक पहचानों के साथ अंतर्संबंध हाशिए पर पड़े समूहों के अनुभवों में जटिलता की परतें जोड़ता है। डिजिटल युग ने जाति की गतिशीलता को और बदल दिया है, जातिवाद को संबोधित करने के लिए चुनौतियाँ और अवसर दोनों पेश किए हैं। जाति-आधारित असमानताओं से निपटने के प्रयास बहुआयामी होने चाहिए, जिसमें कानूनी ढाँचे, सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ और सामाजिक जागरूकता अभियान शामिल हों। जबकि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जाति-आधारित भेदभाव की निरंतरता निरंतर सतर्कता और सक्रिय उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। समाजशास्त्रीय शोध इन मुद्दों को प्रलेखित करने, नीतिगत निर्णयों को सूचित करने और सामाजिक न्याय की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंततः, जातिवाद के उन्मूलन के लिए समानता, न्याय और मानवीय गरिमा के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। जाति व्यवस्था की गहरी प्रकृति को समझकर और उनके द्वारा उत्पन्न समकालीन चुनौतियों का समाधान करके, समाज अधिक समावेशी और न्यायसंगत भविष्य की ओर बढ़ सकता है। जाति पदानुक्रम को खत्म करने और ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर समाजशास्त्रीय जांच और अंतःविषय सहयोग आवश्यक है जहां सभी व्यक्ति अपनी जाति की पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना फल-फूल सकें।

ग्रंथ सूची

- अंबेडकर, बी.आर. जाति का विनाश। बॉम्बे: भीम पत्रिका प्रकाशन, 1936।



- इयूमॉन्ट, लुइस। होमो हिरार्किकस: जाति व्यवस्था और इसके निहितार्थ। शिकागो: यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, 1980।
- श्रीनिवास, एम.एन. आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। बर्कले: यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, 1966।
- बेली, सुसान। अठारहवीं शताब्दी से आधुनिक युग तक भारत में जाति, समाज और राजनीति। कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999।
- डर्क्स, निकोलस बी। जातियाँ मन की: उपनिवेशवाद और आधुनिक भारत का निर्माण। प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2001।
- गुप्ता, दीपांकर। जाति से पूछताछ: भारतीय समाज में पदानुक्रम और अंतर को समझना। नई दिल्ली: पैंगुइन बुक्स, 2000.
- शर्मा, उर्सुला। जाति. बकिंघम: ओपन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999.
- जोधका, सुरिंदर एस. समकालीन भारत में जाति. लंदन: रूटलेज, 2015.
- मेनन, निवेदिता, और आदित्य निगम. सत्ता और प्रतियोगिता: 1989 से भारत. लंदन: जेड बुक्स, 2007.
- तेलतुम्बडे, आनंद. जाति की दृढ़ता: खैरलांजी हत्याएं और भारत का छिपा हुआ रंगभेद. लंदन: जेड बुक्स, 2010.